5

भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप

(NATURE OF THE INDIAN ECONOMY)

इस अध्याय में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में लिखेंगे। इस उद्देश्य के लिए हम निम्नलिखित मुद्दों पर वि[illegible] करेंगे :

- भारतीय अर्थव्यवस्था की वे विशेषताएं क्या हैं जिनके आधार पर उसे अल्पविकसित कहा जा सकता है?
- आर्थिक आयोजन की प्रक्रिया के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक संवृद्धि और संरचनात्मक परिवर्तनों का व[illegible] स्वरूप रहा है? क्या इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था [illegible]

भारत – एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था
(INDIA—AN UNDERDEVELOPED ECONOMY)

इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्पविकसित माना जाता है। हमने अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के जिन लक्षणों की विवेच[illegible] अध्याय 1 में की है, वे लगभग सभी भारतीय आर्थिक ढांचे में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी

1. राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर (Low levels of national and per capita income)— विकसित पूंजीवादी देशों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और जापान की तुलना में भारतीय अर्थप्रणाली हर प्रकार से अल्पविकसित है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 'लोकतन्त्रीय' आर्थिक आयोजन का प्रयोग किया। परन्तु आर्थिक आयोजन के लगभग छः दशक पूरे हो चुकने के बाद भी स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है। आज विकसित देशों और भारत की प्रति व्यक्ति आय में पहले की तुलना में अन्तर अधिक है। इस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की लगभग 1/45 है। इसमें संदेह नहीं है कि विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय से सम्बन्धित आंकड़ों के पारिभाषिक आधार अलग-अलग हैं और इसलिए वे तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से ठीक नहीं हैं। अतः राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना के लिए क्रयशक्ति समता अनुमानों (Purchasing Power Estimates) का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि मध्यम श्रेणी आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की दो से पांच गुनी है। इतना ही नहीं, इस समय अल्पविकसित देशों में भी प्रति व्यक्ति आय के स्तर की दृष्टि से भारत का स्थान बहुत नीचा है। *World Development Report*

World Bank, *World Development Report 2010*, Table I, pp. 378-9.

Scanned with CamScanner

2010 के अनुसार 2008 में भारत का क्रय शक्ति समता में मापित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP per capita measured at Purchasing Power Parity) 2,960 डालर था जबकि अमेरिका में यह 46,970 डालर था।

2. आय का अन्यायपूर्ण वितरण (Inequitable distribution of income)—भारत में आय और सम्पत्ति का वितरण अन्यायपूर्ण है। *Human Development Report* 2007/08 के अनुसार 2004-05 में जनसंख्या के निम्नतम 10 प्रतिशत का सकल घरेलू व्यय में हिस्सा मात्र 3.6 प्रतिशत था जबकि सबसे धनी 10 प्रतिशत का हिस्सा 31.1 प्रतिशत था। यदि हम सबसे निर्धन 20 प्रतिशत जनसंख्या के हिस्से को देखें तो यह 2004-05 में केवल 8.1 प्रतिशत था जबकि सबसे धनी 20 प्रतिशत का हिस्सा 45.3 प्रतिशत था। इस प्रकार, सबसे धनी 20 प्रतिशत और सबसे निर्धन 20 प्रतिशत के व्यय का अनुपात 5.6 था। सबसे धनी 10 प्रतिशत और सबसे निर्धन 10 प्रतिशत के व्यय का अनुपात तो और भी ज्यादा 8.6 था। इन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में आय व व्यय में अत्यधिक असमानताएँ हैं। वर्ष 2004-05 में गिनी सूचकांक (Gini index) 36.8 था (गिनी सूचकांक का मान शून्य होने पर पूर्ण समानता (absolute equality) और 100 होने पर पूर्ण असमानता (absolute inequality) होती है)।[2]

3. व्यापक गरीबी (High incidence of poverty)—आय की असमानताओं से जुड़ी हुई समस्या आम लोगों की गरीबी है। छठी योजना के मसौदे में योजना आयोग ने स्वीकार किया कि 1979-80 में ग्रामीण क्षेत्रों में 50.7 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 40.3 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे थी। दोनों क्षेत्रों को मिला कर देखें तो 48.44 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे थी।[3]

योजना आयोग के अनुसार, 1993-94 में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या कम होकर 36.0 प्रतिशत रह गई (ग्रामीण क्षेत्रों में 37.3 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 32.4 प्रतिशत)।[4] अब नवीनतम आंकड़े वर्ष 2004-05 के लिए उपलब्ध हैं (जो राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण के 61वें दौर पर आधारित हैं)। इन अनुमानों के अनुसार, यदि **समान याददाशत अवधि** (Uniform Recall Period) विधि का प्रयोग किया जाए तो 2004-05 में देश की 27.5 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे थी। 'समान याददाशत अवधि' विधि में सभी उपभोग वस्तुओं के लिए 30 दिन की याददाशत अवधि को लिया गया है। यदि **मिश्रित याददाशत अवधि** (Mixed Recall Period) विधि का प्रयोग किया जाए तो 2004-05 में देश की 21.8 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे थी।[5] 'मिश्रित याददाश्त अवधि' विधि में 5 अखाद्य मदों (non-food items) के लिए 365 दिन की याददाशत अवधि ली गई है (ये 5 मदें हैं—वस्त्र, जूते-चप्पल, टिकाऊ वस्तुएँ, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा व्यय)। अन्य वस्तुओं के लिए 30 दिन की याददाश्त अवधि ली गई है। परन्तु गणना की विधि में परिवर्तन होने के कारण, ये अनुमान पिछले अनुमानों से तुलनीय नहीं हैं।

ऊपर दिए गए अनुमानों से स्पष्ट है कि पिछले कुछ दशकों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में कमी हुई है। परन्तु जनसंख्या में व्यापक वृद्धि के परिणामस्वरूप गरीबों की कुल संख्या अत्यधिक है।

4. कृषि की प्रधानता (Predominance of agriculture)—भारत में जनसंख्या का व्यावसायिक आधार पर विभाजन संतोषजनक नहीं है और यह देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का प्रमाण है। **1951 में कुल 24.9 करोड़ व्यक्ति जो इस समय की कुल जनसंख्या के 70 प्रतिशत थे, कृषि पर अपनी जीविका के लिए निर्भर थे।** योजना-अवधि के पहले चार दशकों में स्थिति में बहुत कम परिवर्तन हुआ और 1991 में 66.9 प्रतिशत लोग कृषि में लगे हुए थे। राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण तथा श्रम मंत्रालय के अनुसार 1990 के दशक में कृषि जनसंख्या की निर्भरता में कमी आई और 2001 में कृषि में 56.7 प्रतिशत लोग कार्यरत थे। परन्तु इतना तो स्पष्ट है ही कि अभी भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में, कृषि पर अत्यधिक लोग कार्यरत हैं और कृषि रोजगार का मुख्य साधन है।

कृषि की प्रधानता जानने की दूसरी विधि भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है। 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद का 17.0 प्रतिशत कृषि से प्राप्त हुआ। निश्चय ही यह 1950-51 की तुलना में बहुत कम है जब कृषि से सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हुआ था। परन्तु यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती क्योंकि इस देश में योजनाओं को शुरू हुए लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं। हमने सारणी 5.1 में कुछ विकसित तथा कुछ विकासशील देशों के लिए वर्ष 2008 के सकल घरेलू उत्पाद के उद्योगवार आंकड़ें प्रस्तुत किए हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में कृषि पर निर्भरता कई विकासशील देशों यथा इंडोनेशिया, चीन, मेक्सिको, तथा ब्राजील की अपेक्षा काफी अधिक है।

2. United Nations Development Programme, *Human Development Report*, 2007-08, Table 15, pp. 281-4.
3. Government of India, Planning Commission, *Sixth Five Year Plan 1980-85* (New Delhi, 1980), p. 52.
4. Government of India, Planning Commission, *Ninth Five Year Plan* Volume I (Delhi, 1999), Table1.9, p. 27.
5. Government of India, *Economic Survey 2007-08* (New Delhi, 2008), Table 10.4, p 243.

Scanned with CamScanner

सारणी 5.1 : उद्योगवार सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत, 2008

देश	कृषि	उद्योग	सेवाएं
इंग्लैंड	1	23	76
जर्मनी	1	30	69
फ्रांस	2	21	77
दक्षिण कोरिया	3	37	60
मैक्सिको	4	37	59
ब्राजील	7	28	65
चीन	11	49	40
इंडोनेशिया	14	48	37
भारत	18	29	53

स्रोत : World Bank, *World Development Report 2010*, Table 4, pp. 384-5.

5. जनसंख्या में तेज वृद्धि और ऊंचा निर्भरता अनुपात (Rapid growth of population and high dependency ratio)—अधिकांश अल्पविकसित देशों की भांति भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। **भारत में 1961 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 43.9 करोड़ थी। 2001 की जनगणना के अनुसार यह 102.9 करोड़ थी। जनसंख्या में वृद्धि जीवन निर्वाह के साधनों के लिए अतिरिक्त मांग उत्पन्न कर विकास कार्य में बाधक होती है।** जे. जे. स्पेंगलर (J.J. Spengler) के अनुसार, "जनसंख्या में वृद्धि से भूमि और कच्चे पदार्थों के स्रोतों के साथ जनसंख्या का अनुपात ऊंचा हो जाता है, फलतः सम्बन्धित उद्योगों में प्रति इकाई परिवर्ती लागत के साथ उत्पादन गिर जाने की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है।"[6] भारत में जनसंख्या में होने वाली लगातार वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति भूमि गिरती जा रही है। जहां 1921 में खेती के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 0.444 हैक्टर थी, वहां 1961 में यह केवल 0.296 हैक्टर, और 2001 में 0.163 हैक्टर थी। स्पष्ट है कि अल्पविकसित देश में जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, उसको उत्पादन कार्य में लगाने के लिए पर्याप्त तेजी के साथ उद्योगों का विकास नहीं होता। नतीजा यह होता है कि भूमि पर जनसंख्या का भार और प्रच्छन्न बेरोजगारी में वृद्धि होती है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी कितनी है, यह वर्तमान सांख्यिकी रीतियों द्वारा सहज नहीं जाना जा सकता। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अनुमान के अनुसार भारत में यह 20 प्रतिशत में 25 प्रतिशत तक हो सकती है। भारत में तेजी के साथ जनसंख्या वृद्धि की वजह से यहाँ का निर्भरता-अनुपात (dependency ratio) भी ऊंचा है।

6. पूँजी का अभाव (Scarcity of capital)—आर्थिक विकास की गति को तेज करने वाले कारकों में पूँजी की भूमिका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। किसी देश में पूँजी का संचय ही उस देश की अर्थव्यवस्था को उसके पिछड़ेपन से मुक्ति दिला सकता है। कुजनेत्स (S. Kuznets) का मत है कि **पूंजी निर्माण के नीचे अनुपात के फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की दर नीची होती है जब तक कि पूँजी-उत्पादन (capital-output) अनुपात गिरने की प्रवृत्ति न दिखलाए।[7] कहने का अर्थ यह है कि देश में तेजी के साथ विकास के लिए भारी मात्रा में पूँजी का निर्माण होना आवश्यक है।** भारत में 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8.6 प्रतिशत भाग बचाया गया और सकल निवेश (gross investment) सकल घरेलू उत्पाद का 8.4 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि बचत तथा निवेश के इस स्तर पर प्रति व्यक्ति आय को स्थिर रख भी पाना भी कठिन था। इतनी थोड़ी बचत का कारण केवल जनसाधारण की गरीबी नहीं हो सकता। वस्तुतः संसार में कोई भी देश इतना गरीब नहीं है कि सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत भाग बचत कर निवेश न कर सके। जब सभी देश युद्ध संचालन के लिए भारी मात्रा में साधनों की व्यवस्था कर लेते हैं तो वे आर्थिक विकास के लिए भी बचत कर सकते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि भारत में बचत का स्तर इतना नीचा क्यों था। दरअसल इसके कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी प्रकार के थे जिनमें पूँजीवादी क्षेत्र का छोटा आकार और भारतीय जमींदारों द्वारा विलासिता के पदार्थों पर फिजूलखर्च विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। इस समय 1950-51 की तुलना में बचत और निवेश दोनों ही स्तर ऊंचे हैं। 1990-91 में बचत का स्तर सकल घरेलू उत्पाद का 22.8 प्रतिशत था जबकि निवेश का स्तर 26.0 प्रतिशत।

[6] J.J. Spengler, "Population Change : Cause, Effect, Indicator", *Economic Development and Cultural Change*, April 1961, p. 253.

[7] S. Kuznets, *Six Lectures on Economic Growth* (Gl...

Scanned with CamScanner

2001-02 में बचत दर 23.7 प्रतिशत तथा निवेश दर 23.8 प्रतिशत थी। बचत और निवेश के इन स्तरों पर आर्थिक संवृद्धि की दर मामूली ही रहेगी। इस तरह यह स्पष्ट है कि भारत में आर्थिक संवृद्धि की दर क्यों ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाई। लेकिन केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने हाल में 2002-03 एवं उसके बाद के वर्षों के लिए बचत और निवेश के जो अनुमान घोषित किए हैं वे पूरी तरह विस्मयकारी हैं। 2002-03 में सकल घरेलू बचत दर बढ़ कर 26.3 प्रतिशत तथा 2007-08 में 37.7 प्रतिशत हो गई (2001-02 से 2007-08 के बीच छः वर्षों में 14 प्रतिशत बिन्दु वृद्धि)। सकल घरेलू पूंजी निर्माण दर भी 2002-03 में बढ़कर 25.2 प्रतिशत तथा 2007-08 में 39.1 प्रतिशत हो गई (छः वर्षों में 16 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि)। ये अनुमान संदेहजनक लगते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने बचत दर एवं निवेश दर के आकलन की रीति को दोषपूर्ण बताया है। आर. नागराज ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि हाल के वर्षों में निजी निगम क्षेत्र की बचत दर में तेज़ वृद्धि हुई है (2002-03 में निजी निगम क्षेत्र की बचत दर सकल घरेलू उत्पाद की 3.9 प्रतिशत थी जो 2007-08 में बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गई)। परन्तु निजी निगम क्षेत्र में बचत एवं निवेश के अनुमान की विधि दोषपूर्ण है और इसके परिणामस्वरूप बचत व निवेश दरों में वृद्धि हुई है।[8]

भारत की तुलना में पूर्व-एशियाई देशों में संवृद्धि दर काफी ऊंची रही है। इन सभी देशों में लम्बे अर्से तक बचत और निवेश दरें नियमित रूप से सकल घरेलू उत्पाद की 35 प्रतिशत से अधिक रही हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ 1997 से 2003 की अवधि में भारत में सकल बचत दर औसतन 23.5 प्रतिशत प्रति वर्ष रही, वहाँ यह कोरिया गणराज्य में औसतन 35.2 प्रतिशत तथा चीन में 39.2 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, जहाँ 1997 से 2003 की अवधि में भारत में सकल निवेश दर औसतन 24.0 प्रतिशत थी, वहाँ कोरिया गणराज्य में यह औसतन 27.1 प्रतिशत तथा चीन में 38 प्रतिशत थी।[9] **बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दरें अर्थव्यवस्था में आर्थिक संवृद्धि दर को तेज रखती हैं। इनके द्वारा नवीनतम तकनीकों का प्रयोग संभव होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है।**

7. मानव विकास का नीचा स्तर (Low level of human development)—मानव विकास का माप प्रायः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) की सहायता से किया जाता है। **मानव विकास सूचकांक मानव विकास के तीन आधारभूत सूचकों — आयु, ज्ञान और जीवन-संभावना का मिश्रण है।** आयु का माप जन्म के समय जीवन-संभावना के रूप में किया जाता है। ज्ञान (अथवा शिक्षा सम्बन्धी उपलब्धि) को प्रौढ़ शिक्षा (दो-तिहाई भार) और सकल दाखिला अनुपातों (एक-तिहाई भार) द्वारा मापा जाता है। जीवन स्तर का माप प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (डालर में क्रय शक्ति समता) के रूप में होता है। क्योंकि मानव विकास सूचकांक जीवन संभावना सूचकांक, शिक्षा उपलब्धि सूचकांक और समायोजित प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक का साधारण औसत होता है, अतः इसे मालूम करने के लिए तीनों सूचकांकों के योग को तीन से विभाजित करना होता है।

सारणी 5.2 में कुछ विकसित और अल्पविकसित देशों के 2007 के लिए मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से देश का स्थान, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, और मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में अंतर को प्रकट करने वाले आंकड़े दिए गए हैं। इस सारणी से स्पष्ट है कि 2007 में भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.612 था। इस दृष्टि से विश्व में इस वर्ष भारत का स्थान 134वां था। श्रीलंका और चीन मानव विकास सूचकांक मूल्य की दृष्टि से भारत की तुलना में ऊपर थे, क्योंकि उनके मानव विकास सूचकांक मूल्य क्रमशः 0.759 और 0.772 थे।

8. बेरोजगारी (Unemployment)— **भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक शोचनीय बात यह है कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।** 1966 में बेरोजगार लोगों की संख्या 2 करोड़ 20 लाख के लगभग थी। भारत में इसके बाद कुछ समय तक आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए। अवधारणात्मक आपत्ति उठाकर सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े देना बन्द कर दिया। छठी पंचवर्षीय योजना में सामान्य स्थिति (Usual status) बेरोजगारी के अलावा साप्ताहिक और दैनिक स्थिति (Weekly and Daily status) बेरोजगारी के भी अनुमान दिए गए हैं। योजना आयोग के अनुसार मार्च 1980 में लगभग 1.20

8. R. Nagaraj, "Recent Economic Growth : A Closer Look", *Economic and Political Weekly*, April 12, 2008, p. 60. भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा, 2009-10, के अनुसार, 2004-05 के आधार पर तैयार की गई नई शृंखला में 2007-08 में बचत दर 36.4 प्रतिशत थी। इस प्रकार, पुरानी शृंखला में 1.3 प्रतिशत का अधि-मूल्यन (over-estimation) था। नई शृंखला के अनुसार, 2008-09 में बचत दर केवल 32.5 प्रतिशत थी जबकि निवेश दर केवल 34.9 प्रतिशत थी। देखें Government of India, *Economic Survey 2009-10*, Table 1.6, pp. A10 and A11.

9. Rajesh Mehta and Manmohan Agarwal, "India: The State of its Economy," in Sankar Kumar Bhaumik (ed.), *Reforming Indian Agriculture* (New Delhi, 2008), Table 1.3, p. 10.

Scanned with CamScanner

सारणी 5.2 : मानव विकास सूचकांक-कुछ विकसित और अल्पविकसित देशों के लिए (वर्ष 2007)

देश	मानव विकास सूचकांक मूल्य 2007	मानव विकास सूचकांक देश का स्थान 2007	प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (डालर में क्रयशक्ति समता) 2007	प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर स्थान और मानव विकास सूचकांक के आधार पर स्थान में अंतर*
विकसित देश				
नार्वे	0.971	1	53,433	4
फ्रांस	0.961	8	33,674	17
जापान	0.960	10	33,632	16
अमेरिका	0.956	13	45,590	– 4
इंग्लैंड	0.947	21	35,130	– 1
विकासशील देश				
क्यूबा	0.863	51	6,876	44
मैक्सिको	0.854	53	14,104	5
मलेशिया	0.829	66	13,518	– 5
ब्राजील	0.813	75	9,567	4
चीन	0.772	92	5,383	10
श्रीलंका	0.759	102	4,243	14
मिस्र	0.703	123	5,349	– 20
भारत	0.612	134	2,753	– 6
बंगलादेश	0.543	146	1,241	9
इथोपिया	0.414	171	779	0

* धनात्मक अंक का अर्थ है कि देश का मानव विकास सूचकांक के आधार पर स्थान प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (डालर में क्रयशक्ति समता) के आधार पर स्थान की तुलना में ऊंचा है। ऋणात्मक अंक का अर्थ उल्टा है।

स्रोत : UNDP, *Human Development Report 2009* (Delhi : Oxford University Press, 2009): Table H, pp. 171-4.

करोड़ लोग स्थायी रूप से बेरोजगार थे। इनकी संख्या मार्च 1990 में 1.30 करोड़ थी। अनुमान है कि अप्रैल 1993-94 में लगभग 10.45 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या बेरोजगारी या अल्प रोजगार की श्रेणी में थी। राष्ट्रीय सैंपिल सर्वेक्षण के 61वें दौर के अनुसार भारत में 2004-05 में 8 प्रतिशत ग्रामीण कार्यशील पुरुष जनसंख्या तथा 8.7 प्रतिशत कार्यशील महिला जनसंख्या दैनिक स्थिति बेरोजगार थी। इसी वर्ष शहरी क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत पुरुष कार्यशील जनसंख्या तथा 11.6 प्रतिशत महिला कार्यशील जनसंख्या बेरोजगार थी। दैनिक स्थिति बेरोजगारी के आंकड़ों के अध्ययन से यह पता लगता है कि 1999-2000 से 2004-05 के बीच बेरोजगारी स्तर में 9-10 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।[10] पश्चिम में पूँजीवादी देशों में बेरोजगारी का स्वरूप चक्रीय (cyclical) है। व्यापार चक्र (business cycle) की मन्दी अवस्था में तो लोग काफी संख्या में बेरोजगार होते हैं, परन्तु समृद्धि की स्थिति में केवल घर्षणात्मक बेरोजगारी (frictional unemployment) होती है। **भारत में बेरोजगारी स्थायी है और इसका कारण अर्थव्यवस्था का दोषपूर्ण गठन है।** गांवों में अनेक व्यक्तियों के पास वर्ष भर काम नहीं है। काफी लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। रेगनर नर्क्स का विचार है कि यदि इस प्रकार के बेरोजगार व्यक्तियों को खेती से हटा लिया जाए तो उत्पादन में वृद्धि होगी। यदि किसी प्रकार इन लोगों को उत्पादन में होने वाली वृद्धि का उपभोग करने से रोका जा सके तो देश में पूँजी निर्माण अधिक हो सकता है। शहरी बेरोजगारी के दो रूप हैं। प्रथम, औद्योगिक क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास नहीं हो पाया है कि बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या को रोजगार मिल सके। इस प्रकार, औद्योगिक बेरोजगारी की समस्या पैदा हुई है। दूसरे, सामान्य शिक्षा के प्रसार से सफेदपोश नौकरियों की मांग में वृद्धि हुई है जिसे देश का शहरी क्षेत्र पूरा कर पाने में असमर्थ रहा है। इससे शिक्षित बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है।

...India, *Economic Survey* 2006-2007 (Delhi, 2007), Table 10.5, p. 210.

Scanned with CamScanner

9. तकनीक का पिछड़ापन (Tehnological backwardness)—यद्यपि विकास प्रक्रिया में तकनीकी प्रगति का बुनियादी योगदान होता है, फिर भी भारत में अभी भी उत्पादन कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक पिछड़े हुए हैं। कृषि में, जो देश की आधे से अधिक जनसंख्या के लिए जीवन निर्वाह की व्यवस्था करती है, उत्पादन तकनीक प्रायः अत्यधिक पिछड़े हैं। देश में हरित क्रान्ति के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर आज भी सदियों पुरानी तकनीकों की सहायता से खेती की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसान ने अज्ञानता के कारण आधुनिक तकनीकों को नहीं अपनाया है। आधुनिक तकनीक, उत्पादन का पैमाना बड़ा-छोटा कुछ भी हो, अपनाए जा सकते हैं, लेकिन उनको अपनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, वे छोटे और सीमान्त किसानों के पास नहीं होते। तात्पर्य यह है कि अधिकांश किसान अपनी गरीबी के कारण नई तकनीकों को अपनाने में असफल रहे हैं। बड़े पैमाने पर स्थापित उद्योगों, ऊर्जा, परिवहन और संचार क्षेत्रों में आधुनिक उत्पादन तकनीकों को अपनाया गया है। लेकिन फिर भी विकसित देशों में अपनाए गए अत्यधिक कुशल उत्पादन तकनीकों और हमारे देश में प्रयोग में आने वाले तकनीकी में काफी अन्तर हैं। पिछले कई दशकों में इस देश में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जो काम हुआ है उससे यहां की तकनीकी क्षमता काफी बढ़ी है और यदि अब इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो देश आर्थिक विकास के सामने आने वाली एक बड़ी बाधा पर काबू पा सकता है।

Scanned with CamScanner